भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

आर्थिक कार्य विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1148

(जिसका उत्तर सोमवार, 02 दिसम्बर, 2024/11अग्रहायण, 1946 (शक) को दिया जाना है)

सेन्ट्रल बैंक डिजिटल करेंसी (सीबीडीसी) को बढ़ावा

1148. श्री संजय हरिभाऊ जाधवः

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार बैंकिंग क्षेत्र में सेन्ट्रल बैंक डिजिटल करेंसी (सीबीडीसी) के उपयोग को बढ़ावा दे रही है;
(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ग) इस संबंध में बैंकिंग क्षेत्र से प्राप्त प्रतिक्रियाओं का ब्यौरा क्या है;
(घ) क्या यह सच है कि सीबीडीसी के अंतर्गत किए गए लेन-देन अज्ञात होते है;
(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और
(च) सीबीडीसी सुविधा का उपयोग करने वाले ग्राहकों की निजता और गोपनीयता सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

वित्त राज्य मंत्री (श्री पंकज चौधरी)

(क) से (ग): न तो सीबीडीसी-रिटेल और न ही सीबीडीसी-व्होलसेल को अंतिम रूप से शुरू किया गया है। भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने 1 नवंबर, 2022 को थोक खंड (ई ₹-डब्ल्यू) में और 1 दिसंबर, 2022 को खुदरा खंड (ई ₹-आर) में डिजिटल रुपये के लिए प्रायोगिक (पायलट) शुरूआत की है। बैंकों ने सीबीडीसी पायलट का हिस्सा बनने में रुचि दिखाई है। इस पायलट की चार बैंकों के साथ शुरुआत की गई और वर्तमान में, 16 बैंक इसमें भाग ले रहे हैं।

(घ) से (च): नीतिगत दृष्टिकोण से, सीबीडीसी-रिटेल, जो नकदी की डिजिटल प्रतिकृति है, में नकदी के समान विशिष्टता होनी चाहिए, जिसमें अनुमेय सीमाओं के भीतर अनामिकता की विशेषता भी शामिल है। तथापि, चूंकि वर्तमान में यह प्रायोगिक चरण में है, इसलिए सीबीडीसी-रिटेल प्रौद्योगिकी संरचना में कई डिज़ाइन संबंधी विकल्पों का परीक्षण कर रहा है, जिसमें अनामिकता और गोपनीयता संबंधी विचार शामिल हैं। इसके अलावा, सभी पायलट बैंक सीबीडीसी सुविधा का उपयोग करने वाले ग्राहकों की निजता और गोपनीयता सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कदम उठा रहे हैं।

****